

15.14 hrs.

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE LAWS (REPEAL) BILL, 2004

Title: Discussion on the Customs and Central Excise Laws (Repeal) Bill, 2004. (Bill passed)

MADAM CHAIRMAN : Now, the House will take up item No. 13 - Customs and Central Excise Laws (Repeal) Bill.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): With your permission, I beg to move:

"That the Bill to repeal certain Customs and Central Excise enactments, be taken into consideration."

This is a very simple Bill. Some Acts had become redundant and obsolete. An expert group was constituted in the Department of Revenue to review existing laws, rules, and regulations. This group has recommended that these enactments may be repealed and they are listed in the Annexure to the Bill. When examined, it was found that the Customs and Central Excise Laws (Amendment) Act of 1988 had introduced certain sections to establish an appellate tribunal but the tribunal was not set up. Subsequently, of course, the Customs Act was amended to set up the tribunal but these provisions were also redundant and obsolete. Therefore, these redundant provisions and the redundant Acts are sought to be repealed so that they do not remain in the statute book and clutter the statute book. Therefore, this is a non-controversial Bill. I would humbly appeal to all hon. Members to join in passing this Bill.

MADAM CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to repeal certain Customs and Central Excise enactments, be taken into consideration."

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदया, मेरा इस सम्बन्ध में यह अनुरोध है कि सरकार जितने भी निरसन करने वाले विधेयक हैं, उनके बारे में कानूनविदों से जानकारी प्राप्त करके एकसाथ उनको लाए। ऐसे कानून जो अब अनुपयोगी हो गए हैं, जिन कानूनों का वर्चस्व नहीं रह गया है, ऐसे कानूनों को विधि आयोग और विधि मंत्रालय के विशेषज्ञों से बात करके, सबको सूचीबद्ध करके, एकसाथ सबका निरसन कर दिया जाए ताकि सदन का समय बच सके।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदया, मैं भी इसमें एक सुझाव देना चाहता हूँ। मंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से ऐसा विधेयक पेश किया है, जिस पर विवाद नहीं है। जब यह पहले वित्त मंत्री थे, उस समय पी.सी. जैन कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने न केवल वित्त विभाग से सम्बन्धित ऐसे कानूनों को बल्कि अन्य विभागों से भी सम्बन्धित अनुपयोगी कानूनों के बारे में कहा था कि ये कानून अब अनुपयोगी हो गए हैं, इनको खत्म कर देना चाहिए। उस समय उन्होंने करीब 148 ऐसे कानूनों को सूचीबद्ध किया था और उनका प्रकाशन किया था। इसलिए सरकार उन सभी कानूनों को रिपील करने के लिए एक विधेयक यहां लाए।

वित्त मंत्री जी बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्व और सीमा शुल्क में करने वाले हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि भविय में राज्यों के अधिकार, खासकर आर्थिक मामलों में और कर निर्धारण के मामले में, इस बहाने से हड़पा या छीना नहीं जाना चाहिए। अभी केन्द्रीय वित्त मंत्री जी की राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। वे लोग कहते हैं कि जो कराधान के प्रावधान हैं, खासकर सेवा कर, उसमें राज्यों का 50 प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए।

भारत सरकार अपना कर दायरा बढ़ा रही है, लेकिन जो राज्यों के कर दायरे हैं, उसमें वह हस्तक्षेप कर रही है। यह प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। आप वैट लागू करने जा रहे हैं। व्यापारियों में इसका काफी विरोध हो रहा है। लेकिन बहुराष्ट्रीय कम्पनीज और इस देश के बड़े उद्योगपतियों का आग्रह है कि इस प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को छोड़ कर सभी राज्य सरकारें इस पर समहत हो गई हैं। उत्तर प्रदेश को संतुष्ट करने में वित्त मंत्री जी की अहम भूमिका है। लेकिन उसके बावजूद हम आग्रह करना चाहेंगे कि भविय में राजस्व और सीमा शुल्क के बारे में जो कराधान प्रावधान हैं, उनके चलते राज्य सरकारों को

शिकायत नहीं होनी चाहिए कि उनके अधिकारों में भारत सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है या उनका अपहरण करना चाहती है। अर्थ के बारे में राज्य सरकारें भारत सरकार की मुखापेक्षी हो जाएं, तो यह स्थिति ठीक नहीं होगी।

इन सुझावों के साथ मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

SHRI P. CHIDAMBARAM : Madam, I take note of the suggestion that the laws mentioned by this Finance Commission and the Review Committee as laws which deserve to be repealed must be repealed soon. You will kindly appreciate that each Ministry has to bring a Bill to repeal the respective laws. I shall certainly pass on the suggestion to my colleagues in the Ministry and ask them to bring Bills to repeal the laws which are obsolete.

As regards the suggestion of another hon. Member, I think, we have started a new chapter by involving the State Finance Ministers in major fiscal policy changes. Only yesterday I held a meeting with State Finance Ministers on service tax. I have held three rounds of meetings with State Finance Ministers on VAT. I have met the Chief Minister of Uttar Pradesh. He is now on board. All the States have agreed that VAT will be implemented. I will continue this practice of consulting the State Finance Ministers in respect of major tax reforms and fiscal changes.

MADAM CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to repeal certain Customs and Central Excise enactments, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MADAM CHAIRMAN : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MADAM CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.
